युद्धके बीच संवादका संदेश

युद्धके इस दौरमें शान्तिके लिए सभ्यताओंके बीच संवादको रेखांकित करते हुए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने जो वैश्विक सन्देश दिया है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जायगा। दिल्ली स्थित पुराना किलामें पहले शंघाई सहयोग संघटन (एससीओ) सभ्यतागत संवाद मंचका उद्घाटन करनेके बाद प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीका यह कहना महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे समयमें भारतमें सभ्यतागत सम्बन्धों और सांस्कृतिक जुड़ावकी बातें कर रहे हैं, जब दुनियाभरमें युद्ध और अशान्तिपर चर्चा हावी है। सांस्कृतिक जुड़ाव वैश्विक शान्तिकी सबसे मजबूत गारण्टी है। एससीओके इस पहले मंचका उद्देश्य सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों और संवाद साझेदारोंके बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदानको बढ़ावा देना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक सहयोगसे सदस्य देशोंके बीच सम्बन्ध और मजबूत होंगे। सभ्यता संवादोंको परिभाषित करते हुए प्रधान मंत्रीका यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि साम्राज्योंने दुनियाके नक्शे जरूर बदले हैं लेकिन सभ्यता संवादोंने दुनियाके विचार बदले हैं और उन्हें समृद्ध किया है। इसलिए एससीओको केवल सभ्यता संवादके एक सहारोह मंचके रूपमें नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये विश्वको दिशा देनेका एक मंच बन सकता है। इस सन्दर्भमें प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीका यह सुझाव भी महत्वपूर्ण है कि भारतके संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागारोंमें हजारों वर्षोंकी अमूल्य विरासत आज भी संजोयी हुई है, जिनमें प्राचीन पांडुलिपियां, दुर्लभ ग्रंथ, ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरावशेष हमारे आपसी सभ्यता, संस्कृतिसे जुड़े कई पहलुओंको सामने लाते हैं। इन्हें आज तकनीककी मददसे अमूल्य धरोहरोंको नयी पीढ़ीतक पहुंचा सकते हैं। इससे दुनियामें कहीं भी रहने वाला युवा किसी दूसरे देशकी सांस्कृतिक विरासतको कहीं अधिक गहराईसे समझ सकेगा। आज हमारे पास पहलेसे कहीं अधिक संसाधन है और हमें उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। भारतकी सभ्यता-संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम्पर आधारित है, जो शान्ति और सौहार्दका सन्देश देती है। इसका प्रचार और प्रसार ही वैश्विक शान्तिका एकमात्र विकल्प है। आजके तनावपूर्ण माहौलमें प्रधान मंत्रीका वैश्विक सन्देश मीलका पत्थर साबित होगा। एससीओका यह सभ्यता संवाद मंच नये विचार सामने लायगा और सांस्कृतिक सहयोगके नये अवसर पैदा करेगा। साथ ही साझा सभ्यतागत अनुभव दुनियाको एकजुट करनेमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

राहतकारी फैसला

सर्वोच्च न्यायालयका हालिया फैसला उत्तर प्रदेशके उन हजारों मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियोंके लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्होंने अपने जीवनके महत्वपूर्ण वर्ष अस्थायी, दैनिक वेतन, मास्टर रोल या वर्कचार्जके रूपमें सरकारी व्यवस्थाको दिये हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीशचन्द्र शर्माकी पीठने राज्य सरकारके २०२१ और २०२५ के उन कानूनोंको असंवैधानिक करार देकर रद कर दिया है, जिनके जरिये नियमितीकरणसे पहलेकी सेवाको पेंशनके लिए अर्हक सेवा माननेसे रोका गया था। यह निर्णय केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि उन कर्मियोंके परिश्रम और बुढ़ापेके सुरक्षाके अधिकारकी पुष्टि है। इस पूरे विवादकी जड़ २०१९ के प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामलेमें निहित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालयने वर्कचार्ज प्रतिष्ठानकी सेवा पेंशनके लिए योग्य माननेका निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकारने २०२० के अध्यादेश और २०२१ के कानून तथा फिर २०२५ के कानूनके माध्यमसे अर्हक सेवाकी परिभाषा बदलकर पुरानी सेवाको बहाल करनेका प्रयास किया। न्यायालयने स्पष्ट किया है कि एक बार किसी कर्मचारीको निर्धारित योजनाके तहत नियमित कर दिया जाय तो वह नियमित सेवा व्यवस्थाका हिस्सा बन जाता है और उसकी शुरुआती नियुक्तिकी प्रकृतिका हवाला देकर उसे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभोंसे वंचित नहीं किया जा सकता। इससे लोकनिर्माण, सिंचाई और भूजल जैसे विभागोंको पात्र कर्मचारियोंको सीधा लाभ मिलनेकी उम्मीद जगी है। सर्वोच्च न्यायालयने दावोंके निस्तारणके लिए छह महीनेकी समय-सीमा तय कर प्रशासनिक टालमटोलपर भी अंकुश लगाया है। अधिकारियोंको यह सुनिश्चित करना होगा कि पात्र कर्मियोंके दावोंपर तय अवधिमें निर्णय हो, अस्वीकृतसे पहले सुनवाईका अवसर मिले और कारण लिखित आदेशमें दर्ज हो। अब राज्य सरकार और सम्बन्धित विभागोंका दायित्व है कि इस फैसलेकी भावनाके अनुरूप संवेदनशीलता और तत्परता दिखाये, ताकि सेवानिवृत्त कर्मियोंको अपने अधिकारोंके लिए दर-दर भटकना न पड़े। यह केवल उत्तर प्रदेशके लिए नहीं, बल्कि इसका अनुपालन अन्य राज्योंको भी करना चाहिए।

लोक संवाद

बिहारका बदलता स्वरूप

महोदय,- बिहारकी पहचान अब केवल गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और पिछड़ेपनसे नहीं होगी, बल्कि उद्योग, व्यापार, निवेश और विकासकी नयी संभावनाओंसे भी होगी। कभी बदहाल व्यवस्था, कमजोर आधारभूत संरचना और रोजगारके सीमित अवसरोंके कारण देशभरमें चर्चामें रहने वाला बिहार आज अपनी आर्थिक तस्वीर बदलनेकी दिशामें आगे बढ़ रहा है। मुख्य मंत्री नीतीश कुमारके लम्बे कार्यकालमें आधारभूत सुविधाओंके क्षेत्रमें हुए प्रयासोंका असर अब दिखाई देने लगा है। इसी विकास यात्राको आगे बढ़ाते हुए मुख्य मंत्री सम्राट चौधरी बिहारको देशका प्रमुख औद्योगिक और निर्यात केन्द्र बनानेकी महत्वाकांक्षी योजनापर काम कर रहे हैं। यह केवल आर्थिक विकासका लक्ष्य नहीं है, बल्कि बिहारकी नयी पहचान गढ़नेकी दिशामें महत्वपूर्ण कदम भी है। पटनामें उद्योग विभागकी ओरसे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला लेवरेजिंग एफटीए-आउटरीच प्रोग्राममें मुख्य मंत्री सम्राट चौधरीने स्पष्ट किया कि बिहारकी अर्थव्यवस्थाको मजबूत बनाने और युवाओंके लिए रोजगारके अधिक अवसर पैदा करनेका सबसे प्रभावी माध्यम उद्योगोंका विकास है। सरकारका लक्ष्य बिहारको देशके सबसे तेजीसे औद्योगिकीकरण करने वाले राज्योंमें शामिल करना और अंतरराष्ट्रीय बाजारोंतक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके लिए राज्यमें निवेशको प्रोत्साहित करने, स्थानीय उत्पादोंको वैश्विक पहचान दिलाने और निर्यातकी संभावनाओंको विस्तार देनेकी दिशामें योजनाबद्ध तरीकेसे काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्रीने अपने संबोधनमें बिहारकी दो प्रमुख चुनौतियों आबादी और पानीका उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले दस वर्षोंमें इन दोनोंको राज्यकी ताकतमें बदलना होगा। बिहारके सामने जनसंख्याका दबाव एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन यही आबादी यदि शिक्षित, प्रशिक्षित और रोजगारसे जुड़ जाय तो राज्यकी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकती है। युवाओंको कौशल प्रशिक्षण देकर उद्योगोंकी जरूरतोंके अनुरूप तैयार करना होगा। इसी तरह जल संसाधनोंका उचित उपयोग कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिक गतिविधियोंको नयी गति दे सकता है। राज्यकी आर्थिक प्रगतिका उल्लेख करते हुए मुख्य मंत्रीने बताया कि पिछले बीस वर्षोंसे बिहारकी अर्थव्यवस्थामें दोहरे अंकोंकी विकास दर दर्ज की गयी है। कभी राज्यका बजट लगभग छह हजार करोड़ रुपये हुआ करता था, जो आज बढ़कर तीन लाख ४७ हजार करोड़ रुपयेतक पहुंच गया है। हालांकि बजटका आकार बढ़ना ही विकासका अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। इसका वास्तविक लाभ तभी माना जायगा जब इसका असर आम नागरिकके जीवन, किसानोंकी आय और उद्योगोंकी स्थापनाके रूपमें दिखाई दे। एक समय बिहारकी राजनीतिमें जंगलराज, अपराध, अव्यवस्था और पलायन जैसे मुद्दे प्रमुखतासे चर्चामें रहते थे। नीतीश कुमारके नेतृत्वमें सड़क, बिजली और प्रशासनिक व्यवस्थामें सुधारके प्रयासोंने बिहारको नयी दिशा दी। अब सम्राट चौधरीके नेतृत्वमें औद्योगिकीकरण और निर्यातको विकासका प्रमुख आधार बनानेकी कोशिश की जा रही है। बिहारके सामने सबसे बड़ी आवश्यकता युवाओंको अपने ही राज्यमें रोजगार उपलब्ध करानेकी है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्यामें युवा बेहतर अवसरोंकी तलाशमें दूसरे राज्योंकी ओर पलायन करते हैं। यदि बिहारमें उद्योगोंका विस्तार होता है तो रोजगारके नये द्वार खुल सकते हैं। इससे न केवल पलायनपर अंकुश लगानेमें मदद मिलेगी, बल्कि राज्यकी आर्थिक आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। बिहारको देशका प्रमुख निर्यात केन्द्र बनानेका सपना निश्चित रूपसे बड़ा है। लेकिन इस सपनेको साकार करनेके लिए घोषणाओंके साथ धरातलपर ठोस परिणाम भी जरूरी हैं। यदि सरकार अपनी योजनाओंको समयबद्ध तरीकेसे लागू करनेमें सफल रहती है तो बिहार आने वाले वर्षोंमें वैश्विक बाजारमें पहचान बनाने वाला आर्थिक शक्ति केन्द्र बन सकता है। यही बिहारके उज्ज्वल भविष्यकी वास्तविक कसौटी होगी। **-कांतिलाल मांडोत, वाया ईमेल।**

विश्व कूटनीतिकी बदलती दिशा

भले ही भारत आसियानका पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन यह संघटनके साथ साझेदारी और संवाद तंत्रके माध्यमसे जुड़ा हुआ है। वर्ष १९६७ में स्थापित आसियानमें ब्रूनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलयेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर-लेस्ते शामिल हैं।

❐ पुष्परंजन

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी फिलीपींसके राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियरके निमंत्रणपर मनीलामें आयोजित २३वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और २१वें ईस्ट एशिया समिटमें भाग लेने गये थे। भले ही भारत आसियानका पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन यह संघटनके साथ साझेदारी और संवाद तंत्रके माध्यमसे जुड़ा हुआ है। आसियानकी मशाल अब सिंगापुरके हाथोंमें है। वर्ष १९६७ में स्थापित आसियानमें ब्रूनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलयेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर-लेस्ते शामिल हैं। वर्ष २०२७ में इस क्षेत्रीय समूहकी ६०वीं वर्षगांठ होगी। लेकिन पीएम मोदीका मनीला जाना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि वहां क्वाड समूहकी शिखर बैठक भी साथ-साथ निबट गयी। क्वाडमें अमेरिका, जापान, भारत और आस्ट्रेलिया शामिल हैं। पिछले दिनों क्वाड नेता फिलीपींसकी राजधानी मनीलामें बगलगीर थे। सितंबर २०२४ के बादसे यह उनकी पहली मुलाकात थी। चीनी पर्यवेक्षक इससे चिढ़से गये। 'ग्लोबल टाइम्स' ने उनके हवालेसे तंज किया, यह समूह फोटो डिप्लोमेसीतक ही सीमित है। जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। वजह साऊथ चाइना सी है, जहां चीनके अलावा फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई और ताइवान इस क्षेत्रके अलग-अलग द्वीपों और जलक्षेत्रोंपर अपना दावा जताते रहे हैं। इंडोनेशियाके साथ भी उसके समुद्री क्षेत्रको लेकर मतभेद हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणने २०१६ में फिलीपींसके पक्षमें फैसला देते हुए चीनके ऐतिहासिक दावोंको अंतरराष्ट्रीय कानूनके विरुद्ध बताया था, लेकिन चीन इस फैसलेको नहीं मानता है।



शेनझेनमें आयोजित एपेक शिखर सम्मेलनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसके राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध समाप्त करने, ईरानसे शांतिकी बातपर अमल करते हैं तो शायद बहुध्रुवीय विश्वकी अर्थव्यवस्था पटरीपर आये। ट्रम्पके पास अब नेतन्याहू जैसा उग्र और अहंकारी साथी नहीं है, इसलिए वह इस बार अपने बयानोंके जरिये टैरिफ बम नहीं बरसा रहे हैं। फरवरी २०२६ में अमेरिका और रूसके बीच न्यू स्टार्ट संधि समाप्त होनेके बाद ट्रम्प हथियारोंपर नियंत्रणके लिए नयी और आधुनिक व्यवस्थाकी बात कर रहे हैं।

मनीला शिखर बैठकमें दक्षिण चीन सागरकी आचार संहितापर आसियान देश और चीन अंतिम समझौतेतक नहीं पहुंच सके, हालांकि मसौदेके लगभग ८० प्रतिशत हिस्सेपर अस्थायी सहमति बन चुकी थी। अब शायद सिंगापुर शिखर बैठकमें कुछ हो। फिलीपींसने अपनी आसियान अध्यक्षताके दौरान २०२६ के अंततक इस समझौतेको पूरा करनेका लक्ष्य रखा था, लेकिन मतभेदोंके कारण यह पूरा नहीं हो सका। सिंगापुरके पूर्व राजनयिक बिलाहारी कौसिकन अपनी बेबाक टिप्पणियोंके लिए मशहूर हैं। २०१५ में सिंगापुरमें आयोजित एक सम्मेलनमें बिलाहारीने आसियानकी तुलना 'एक गाय' से की थी, जो 'कभी घोड़ा नहीं बन सकती।' उन्होंने कहा कि दोनों ही जानवर उपयोगी हैं, लेकिन उनकी उपयोगिताका स्तर अलग-अलग है। लेकिन मनीला शिखर बैठकसे बड़ी कूटनीतिक कहानी शेनझेन शिफ्ट कर दी गयी है। १८ से १९ नवंबर २०२६ को २१ सदस्यीय एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन चीनके शेनझेन शहरमें आयोजित हुई। १९ नवंबरको शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रम्प और ब्लादिमीर पुतिनके बीच पहली मुलाकातमें विश्वकी दिशा बदली, ऐसा कुछ पर्यवेक्षक कह रहे हैं। 'एपेक' पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्रमें मुक्त व्यापारको बढ़ावा देता है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है।

अगरचे, यह त्रिपक्षीय बैठक ट्रम्पके नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टीकी शर्मनाक हारकी पृष्ठभूमिमें हो रही है, इसलिए ट्रम्प इसमें अपने लिए एक ही फायदा देखते हैं, जो जरूरी नहीं कि अमेरिकाके लिए भी फायदेमंद हो। वह अपने घरेलू समर्थकोंके सामने यह दावा कर सकते हैं कि मध्यावधि चुनावोंमें हारके बावजूद, 'वह अब भी इतने ताकतवर हैं कि दुनिया चला सकते हैं।' लेकिन ट्रम्पकी छविकी जिस तरह मिट्टी-पलीद हुई है, ट्रम्पकी ऐसी दावेदारीको शायद ही कोई सीरियसली ले। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशनके चाइना सेंटरके फेलो जोनाथन ए. जिनका कहना है कि ऐसी किसी स्थितिकी कल्पना करना मुश्किल है, जिसमें ट्रम्प, शी और पुतिनके बीच बैठकसे अमेरिका और उसके हितोंके लिए कोई अच्छा नतीजा निकला। हालांकि शेनझेनमें त्रिपक्षीय बैठक पुतिनकी हामीके बाद ही तय हुई थी। इस साल मईमें राष्ट्रपति ट्रम्पकी पेइचिंग यात्राके बादसे ही शी-ट्रम्प-पुतिनके बीच एक सम्भावित त्रिपक्षीय बैठकको लेकर अटकलें लगायी गयी थीं। जैसे ही ट्रम्पने पुष्टि की कि वह शेनझेनमें होने वाले एपेक शिखर सम्मेलनमें शामिल होंगे, पुतिनने बिना समय गंवाये फोनपर बातचीतके दौरान अपने अमेरिकी समकक्षके सामने एक संयुक्त बैठकका प्रस्ताव रख दिया। यूक्रेनपर रूसके पूर्ण सैन्य आक्रमणके बादसे उन्हें वर्षोंतक कूटनीतिक अलगाव और बहिष्कारका सामना करना पड़ा था।

ट्रम्पके तेवर भी मध्यावधि चुनाव परिणामके बादसे ढीले लग रहे हैं। मनीलामें पीएम मोदीके साथ उनकी देहभाषा दोस्ताना थी। मनीलामें ट्रम्पने कोई विवादित बयान भी नहीं दिया। मनीलामें पत्रकारोंसे बात करते हुए ट्रम्पने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उनसे मुलाकातकी सम्भावना जतायी। इस बैठकके लिए शेनझेनको चुननेके पीछे रूसकी सोचके बारेमें बताते हुए, वाशिंगटन स्थित स्टिमसन सेंटरकी सुन युन ने कहा, रूस संभवतः इस शिखर सम्मेलनका इस्तेमाल चीन और अमेरिकाको यूक्रेनके मुद्देपर मॉस्कोके रुखके करीब लानेके लिए करेगा। सुनने आगे कहा कि चीन हथियारोंके नियंत्रण, यूक्रेन या ईरान जैसे मुद्दोंपर बातचीतमें शामिल नहीं होगा, वह बस यही कहता रहेगा कि शांति जरूरी है और युद्ध खत्म होने चाहिए। तीनों नेता मिलकर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने, ईरानसे शांतिकी पहल करनेके वास्ते आगे बढ़ते हैं तो शायद बहुध्रुवीय विश्वकी अर्थव्यवस्था पटरीपर आये। ट्रम्पके पास अब नेतन्याहू जैसा उग्र और अहंकारी साथी नहीं है, इसलिए वह इस बार अपने बयानोंके जरिये टैरिफ बम नहीं बरसा रहे हैं। फरवरी २०२६ में अमेरिका और रूसके बीच न्यू स्टार्ट संधि समाप्त होनेके बाद ट्रम्प हथियारोंपर नियंत्रणके लिए नयी और आधुनिक व्यवस्थाकी बात कर रहे हैं।

सवैधानिक निष्ठा अनिवार्य

भारत स्वभावसे ही लोकतंत्रका उपासक है। भारतीय धर्म दर्शनमें सहमति और असहमतिकी सांस्कृतिक निरन्तरता है। भारतको दुनियाके किसी अन्य देशसे प्रेरित होनेकी आवश्यकता नहीं है।

❐ हृदयनारायण दीक्षित

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारतीय राजनीतिसे निराश हैं। जनता उनकी पार्टीको घास नहीं डालती। इसीलिए वे अब अमेरिकाकी शरणमें हैं। वे अमेरिकामें भारतकी बदनामीमें अतिरिक्त सक्रिय हैं। वे भारतमें २०२४ के चुनावको अवैध सिद्ध करनेका अभियान चला रहे हैं। दरअसल २०१४, २०१९ एवं २०२४ के आम चुनावके नतीजे राहुलकी पार्टीके विपरीत रहे। लगातार हारते हुए राहुल गांधी लस्त-पस्त हैं। वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि खुले मनसे हार स्वीकार करें या कांग्रेस मजबूत करें या भारतीय चुनाव प्रणालीको निशानेपर लेते रहें। वे १९ नवंबर २०२६ के दिन अमेरिकाके शिकागो विश्वविद्यालयमें थे। राजनीति विज्ञानके छात्रों और अध्यापकोंको संबोधित करते हुए राहुलने २०२४ के आम चुनावको पूरी तरहसे अवैध ठहराया। वे भूल गये कि इसी विश्वविद्यालयमें भारतीय धर्म दर्शनकी श्रेष्ठतापर स्वामी विवेकानंदने महत्वपूर्ण भाषण दिया था। अच्छा होता कि वे विवेकानंदसे प्रेरणा लेते और यूनिवर्सिटीमें भारतीय लोकतंत्रकी प्रशंसा करते। वे भूल गये कि २०२४ के जिस चुनावको वे अवैध बता रहे हैं, वे स्वयं इसी चुनावके परिणामोंके आधारपर नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित हुए हैं। वह ये भी भूल गये कि वे अमेरिकामें हैं और भारतीय लोकतंत्रकी मूल भावनाको कुठाराघात कर रहे हैं।

राहुलने यह भी कहा है कि कांग्रेसको २०२४ के लोकसभा चुनावके समयसे ही चुनावी गड़बड़ीका अंदेशा था। अब उनके पास सुबूत आ गये हैं। मूलभूत प्रश्न है कि वे देशके बाहर भारतीय चुनावको भ्रष्ट सिद्ध करनेके अभियानको क्यों चला रहे हैं। क्या अमेरिका उनकी बेचैनीका कोई समाधान कर सकता है। क्या हजारों वर्ष प्राचीन संस्कृति वाले राष्ट्र भारतकी चुनाव प्रणालीमें कोई हस्तक्षेप करनेकी स्थितिमें है। इसका उत्तर साफ है कि भारत संप्रभु राष्ट्र है। भारत दुनियाके किसी भी देशके दबाव या प्रभावमें काम नहीं करता। भारत स्वभावसे ही लोकतंत्रका उपासक है। भारतमें वैदिककालसे ही सभा और समितियां हैं। भारतीय धर्म दर्शनमें सहमति और असहमतिकी सांस्कृतिक निरन्तरता है। भारतको दुनियाके किसी अन्य देशसे प्रेरित होनेकी आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र भारतकी जीवनशैली है। राहुल पराजित मानसिकताके कारण वाणी और व्यवहारका समन्वय भी नहीं कर पाते। राहुलकी पार्टी जहां-जहां हारती है वहां-वहां ईवीएमपर आरोप लगाती है। चुनाव आयोगपर भी तथ्यहीन आरोप लगाती है। भारतमें संविधानकी सत्ता है। संविधानको मानना प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य है। राहुल जैसे नेता संविधानका सम्मान नहीं करते। संवैधानिक संस्थाओंपर हमला बोलना, संविधानसे इनकार करना है। संविधानको न मानने वाले भारतके नागरिक नहीं हो सकते। राहुलकी पार्टी संसद चलने नहीं देती। संसद ही सहमति और असहमति व्यक्त करनेका सर्वोपरि संवैधानिक निकाय है। लोकतंत्रमें संवैधानिक निष्ठा अनिवार्य है। लेकिन वे न्यायालयोंकी गरिमाका ध्यान नहीं रखते। भारतीय चुनाव आयोगकी प्रशंसा सारी दुनियामें होती है। इसी अपने चुनाव आयोगकी भर्त्सना निन्दा मर्यादाहीन आचरणको भी पार करती है। हालांकि अमेरिकामें उन्होंने एक प्रश्नके उत्तरमें यह भी कहा है कि भारतीय लोकतंत्र हमारे लिए पवित्र है। उनका बयान उचित है। लेकिन इसी लोकतंत्रको वे लगातार अपमानित कर रहे हैं। चुनाव लड़कर संसद या विधान मण्डलमें पहुंचना प्रत्येक व्यक्तिका अधिकार है। सरकार बनाने चुनावके माध्यमसे यथाविधि सत्ता प्राप्त करनेकी संवैधानिक व्यवस्थाको चुनौती नहीं दी जा सकती। सत्ता अराजकता फैला कर नहीं मिलती है। संविधानका कोई विकल्प नहीं होता। उनकी पार्टीका जनाधार समाप्त हो गया है तो ये उनकी समस्या है। भारत भूमिसे बाहर भारतीय अर्थव्यवस्थाके भरभराके गिर जानेकी घोषणा भी राहुलने की है। वे अर्थशास्त्रके जानकार नहीं हैं।

ब्रिटेनमें भी संसदीय व्यवस्था है। ब्रिटिश संसदमें भी नेता विरोधी दल होते हैं। ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि ब्रिटेनके नेता विरोधी दल दुनियाके किसी भी अन्य देशमें अपनी व्यवस्थाकी निन्दा नहीं करते। ब्रिटेनके राजनीतिक दल लेबर और कंजरवेटिव आपसमें अपने देशके भीतर ही खूब बहस करते हैं। नीतियोंकी आलोचना करते हैं। यूरोपके देशोंमें कोई विपक्षी दल या नेता देशके बाहर देशकी निन्दा नहीं करते। संयुक्त राज्य अमेरिकाकी संघीय व्यवस्था राज्योंकी राजनीतिको तमाम अवसर देती है। वहां दो विपरीत विचारधाराके राजनीतिक दल हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। लेकिन अमेरिकाके किसी विपक्षी नेताने अपने देशके बाहर अपने देशकी निन्दा नहीं की। भारत विशाल लोकतंत्र है। यहांके नेता प्रतिपक्षको हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें उच्च सुशिक्षित अर्थशास्त्रियोंकी सही परामर्श देने वाली एक टीम अपने पास रखनी चाहिए। आयात और निर्यातके आंकड़े भी देखने चाहिए। उनका सम्यक विश्लेषण भी करते रहना चाहिए। वित्तमंत्रीकी तरफसे तमाम आंकड़े दिये गये हैं। प्रधान मंत्रीने भी समय-समयपर अर्थव्यवस्थापर विचार व्यक्त किये हैं। प्राचीन परम्पराके अनुसार राजाको अर्थशास्त्रका ज्ञाता होना चाहिए। महाभारतके प्रसंगमें नारद युधिष्ठिरके राजभवन पहुंचे। उन्होंने युधिष्ठिरसे पूछा कि क्या अर्थचिन्तनके लिए समय निकालते हैं। युधिष्ठिर हा करते हैं। वाल्मीकि रामायणके अनुसार भरत श्रीरामको वापस अयोध्या लानेके लिए वन गये थे। श्रीरामने उनसे कई प्रश्न पूछे। उनमेंसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थशास्त्रके लिए भी था। कौटिल्यने अर्थशास्त्रमें भी अर्थचिन्तनको जरूरी बताया है। यूरोपीय अर्थशास्त्रियोंमें एडम स्मिथ और मार्शल आदिके नाम सम्मान सहित लिये जाते हैं। राहुलको भारतीय अर्थव्यवस्थापर टिप्पणी करते समय प्राचीन प्रसंगोंको आधुनिक संदर्भमें पढ़ना और समझना चाहिए। वोट चोरीका मंत्र और शोर अनुचित है। सबसे बड़ी बात है कि वक्तव्य देनेका उचित समय और उचित स्थान। देशके बाहर ऐसे वक्तव्य देनेसे अपने देशकी ही बदनामी होती है। यह कृत्य संविधान और संस्कृतिका अपमान है। ऐसा कृत्य निन्दनीय है।



संजीवनी सुधा

❐ यशपाल कुमार

पूर्व कालमें जालन्धर नामका एक दैत्य था, तप द्वारा उसे ब्रह्मा जीसे यह वरदान प्राप्त हुआ था कि वह सर्व-विजयी होगा एवं वृन्दा नामकी शिवभक्त कन्याके भक्ति एवं तप बलके प्रभावसे यह किसीके द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। ब्रह्माजीके वरदानसे वृन्दाके नामकी सुशील भक्त, तपस्वी कन्या उसे पत्नी रूपमें सुलभ हुई। अपनी तपस्या एवं वृन्दा पतिव्रत धर्मके प्रभावसे जालन्धरने त्रैलोक्यमें विजय प्राप्त कर ली। एक बार जालन्धर कैलाश पर्वतके मार्गसे जा रहा था, जहां उसने मां पार्वतीको दिगम्बर कैलाश पति आशुतोष भगवान शिवके साथ देखा, मां पार्वतीके सौन्दर्यपर जालन्धर मोहित हो गया एवं उसने भगवान शिवसे मां पार्वतीकी याचना कर डाली। अस्तु! भगवान शंकर एवं जालन्धरमें महान संग्राम छिड़ गया लेकिन ब्रह्मा जीके वरदान एवं वृन्दाके पतिव्रत धर्मके असीम शक्तिसे भगवान शंकरका त्रिशूल भी जालन्धरका कुछ न बिगाड़ सका। भगवान आशुतोष सदा शिवने सृष्टिके पालनकर्ता भगवान श्री हरिका स्मरण किया। श्री हरिने शिवको जालन्धरपर विजयका आश्वासन दिया। जिस वनमें पतिव्रता वृन्दा अपने पति जालन्धरकी जीवन रक्षाके लिए भगवानकी आराधना कर रही थी वहीं अनन्त श्री हरिने एक मायाकी रचना की, श्री हरि साधुका रूप धारण कर ध्यान मगन हो गये एवं जहां देवी वृन्दा भगवान शिवकी आराधनामें लीन थी उसकी गोदमें भगवान श्री हरिकी लीलासे जालन्धरका सिर कटकर गिर पड़ा। देवी वृन्दा ह्विल हो श्री हरिसे लिपटकर रोने लगी। अब साधु वेषधारी भगवान श्री हरि अपने वास्तविक स्वरूपमें प्रकट हो गये। भगवान श्रीहरिको देवी वृन्दाने क्रोधमें आकर श्राप दिया कि जाओ तुम शिला हो जाओ। भक्त वत्सल श्री हरिने वृन्दाको वरदान दिया कि मैं एक रूपसे शिला बनकर शालिग्रामके नामसे भक्तों द्वारा पूजा जाऊंगा, लेकिन तुम यह शरीर त्याग कर तुलसीकी मंजरी बनोगी। तुलसी दल मेरे मस्तकपर गंगाजलके साथ चढ़ेगा। गृहस्थों घरके हर आंगनमें तुम विराजमान रहोगी। जो सद्गृहस्थ अपने आंगनमें तुम्हारी प्रतिष्ठा करेंगे, उन्हें कोई रोग स्पर्श नहीं करेगा। संजीवनी सुधासे वहांका वातावरण सदा सराबोर रहेगा। जो भक्त श्रीकृष्ण शरणम् मम, श्री तुलसी देव्यै नमः। इन मंत्रोंसे तुम्हें प्रणाम करेंगे मेरी कृपा उनके परिवारमें सदा भगवद् भक्ति, सन्मति, शान्ति, धन-धान्य समृद्धिकी प्रतिष्ठा होगी। अमृतदायिनी औषधीय गुणोंसे युक्त तुलसी- तुम अमृत औषधिके रूपमें सर्वदा प्रयुक्त होगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा एवं पूजन करने वालोंको मैं अकाल मृत्यु, सर्व-व्याधियोंसे मुक्त करता रहूंगा। उन्हें सदा सन्मति प्रदान कर अंत समयमें मोक्ष भी प्रदान करूंगा। हर घरमें श्री तुलसी जीके पौधेके रोपणसे वातावरण संजीवनी सुधारसे सराबोर हो जायगा।

रैगिंग नियंत्रणपर शिक्षण प्रशासनपर उठते सवाल

❐ रोहित माहेश्वरी

लखनऊके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटीमें नये छात्रोंके साथ कथित रैगिंगका एक मामला बीते दिनों सामने आया है। इस घटनाका एक वीडियो सोशल मीडियापर वायरल होनेके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसीने संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासनसे जवाब मांगा है। वायरल वीडियोमें एमबीबीएस प्रथम वर्षके छात्र-छात्राएं सफेद एप्रन पहने, हाथ पीछे बांधे और सिर झुकाकर एक कतारमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि परिसरमें कलाम सेंटरके पास सीनियर छात्रोंके गुजरनेपर नये छात्रोंसे तेज आवाजमें 'प्रणाम महोदय जी' और 'प्रणाम मैडम जी' बोलनेके लिए मजबूर किया जा रहा था। यह घटना जिस स्थानपर हुई, वहां सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी कैमरे मौजूद होनेके बावजूद इस तरहका व्यवहार होनेसे कैंपसकी निगरानी व्यवस्थापर सवाल उठाये जा रहे हैं। रैगिंग, यह शब्द पढ़नेमें सामान्य लगता है। इसके पीछे छिपी भयावहताको वे ही छात्र समझ सकते हैं, जो इसके शिकार हुए हैं। आधुनिकताके साथ रैगिंगके तरीके भी बदलते जा रहे हैं। रैगिंग आम तौरपर सीनियर विद्यार्थी द्वारा कालेजमें आये नये विद्यार्थीसे परिचय लेनेकी प्रक्रिया। लेकिन यदि किसी छात्रको रैगिंगके नामपर अपनी जान गंवाना पड़े तो उसे क्या कहेंगे। सीनियर छात्रोंके लिए रैगिंग भले ही मौज-मस्ती हो सकती है, लेकिन रैगिंगसे गुजरे छात्रके जहनसे रैगिंगकी भयावहता मिटती नहीं है।

हालके महीनोंमें उत्तर प्रदेशके लखनऊके अलावा जालौन और झांसी और राजस्थानके कोटा, बाड़मेरके मेडिकल कालेजोंमें रैगिंगके कई गम्भीर मामले सामने आये हैं। इनपर संज्ञान लेते हुए एनएमसी और राज्य सरकारोंने कई छात्रोंको निलंबित किया है और जीरो-टॉलरेंस नीति लागू करनेके निर्देश दिये हैं। कोटा मेडिकल काले